मिज़ोरम में आर्थिक और वित्तीय विकास *

दीपक मोहंती

मुझे खुशी है कि मैं मिज़ोरम राज्य के सुरम्य वातावरण में हूं जहां बलखाती पहाड़ियां हैं, खाड़ी, नदियां और झीलें हैं। यह राज्य बहुत ही अनुकूल स्थान पर है जहां इसकी अधिकांश सीमाएं बांगलादेश और म्यानमार से मिलती हैं। पूरे देश में इसका भौगोलिक क्षेत्र 0.6 प्रतिशत और जनसंख्या 0.1 प्रतिशत है। यह देश का दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है जिसमें आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं हैं।

आर्थिक विकास के लिए वित्त की उपलब्धता महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। हाल के वर्षों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को नये उत्साह के साथ आगे बढ़ाया है। इस दिशा में कुछ प्रगति हासिल हुई है लेकिन अभी भी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय विकास फलक के पांच स्तंभों में से एक स्तंभ वित्तीय समावेशन पर अत्यधिक बल दिया है जो इस प्रकार है - ''देश के लघु और मझौले उद्यमों, असंगठित क्षेत्रों, गरीबों और दूर-दराज तथा बैंक सेवारहित क्षेत्रों में वित्त को प्रौद्योगिकी, नये कारोबारी तरीकों और नये संगठनात्मक ढांचों के माध्यम से पहुंचाया जाए''[1]। उत्तर-पूर्वी राज्यों में वित्तीय समावेशन की चुनौती अधिक है क्योंकि यहां पर बैंकिंग सेवाएं अपेक्षाकृत कम हैं और बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। इस पृष्ठभूमि में, मैं संक्षेप में इस राज्य के आर्थिक और वित्तीय ढांचे का चित्रण करना चाहूंगा, अपनी वित्तीय समावेशन की पहल पर प्रकाश डालूंगा तथा भावी नीतिगत चुनौतियों के बारे में विचार प्रस्तुत करुंगा।

आर्थिक ढांचा

2000 के दशक में भारत के जीडीपी में तेज़ी से वृद्धि हुई। नि:संदेह इस वृद्धि में कई राज्यों की हिस्सेदारी थी। राष्ट्रीय

चार्ट 1 : वार्षिक संवृद्धि प्रवृत्ति

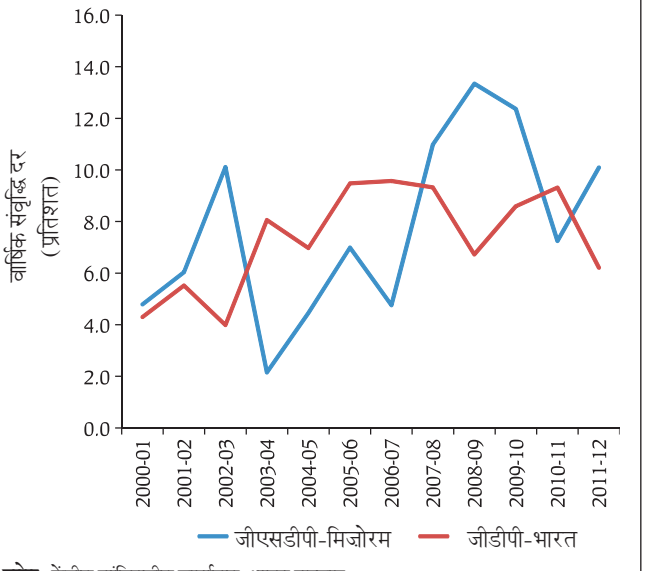

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार

अर्थव्यवस्था के साथ-साथ मिज़ोरम में भी संवृद्धि ने गति पकड़ी। यद्यपि 2007-08 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण राष्ट्रीय वृद्धि का स्तर दब गया था, किंतु संकट के बाद भी मिज़ोरम का आर्थिक निष्पादन बेहतर बना रहा। फलस्वरूप, पूरे भारत में जीडीपी में मिज़ोरम का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2006-07 के 0.08 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 0.10 प्रतिशत हो गया था (चार्ट 1)।

अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्र - कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों ने राज्य के बेहतर संवृद्धि निष्पादन में अपना योगदान दिया है। हालांकि वर्ष-दर-वर्ष क्षेत्रवार संवृद्धि दर से उतार-चढ़ाव होते रहे हैं। कृषि क्षेत्र में कमी-बेशी हो सकती है क्योंकि यह मौसम पर निर्भर होता है, लेकिन औद्योगिक संवृद्धि में अस्थिरता पर अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है क्योंकि राज्य में उद्योग का आधार बहुत कम है (चार्ट 2)।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तरह मिज़ोरम की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार कंपोजीशन में भी काफी बदलाव आया है जिसमें कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है और सेवा क्षेत्र का बढ़ा है। हालांकि उद्योग की हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ी है लेकिन राष्ट्रीय औसत से काफी कम है जो यह दर्शाती है कि औद्योगीकरण को और अधिक बढ़ाए जाने की संभावना है (चार्ट 3)।

---

* श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, 19 दिसंबर 2013 को आइज़ाल क्लब में दिया गया व्याख्यान। इस संबंध में डॉ. पी. के. नायक, एस. सूरज और एस. नाथ द्वारा दिए गए सहयोग के प्रति आभार।

[1] भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय क्षेत्र नीति के पांच स्तंभ, रघुराम जी. राजन, गवर्नर द्वारा 15 नवंबर 2013 को मुंबई में बैंकान में दिया गया व्याख्यान। भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, दिसंबर 2013।

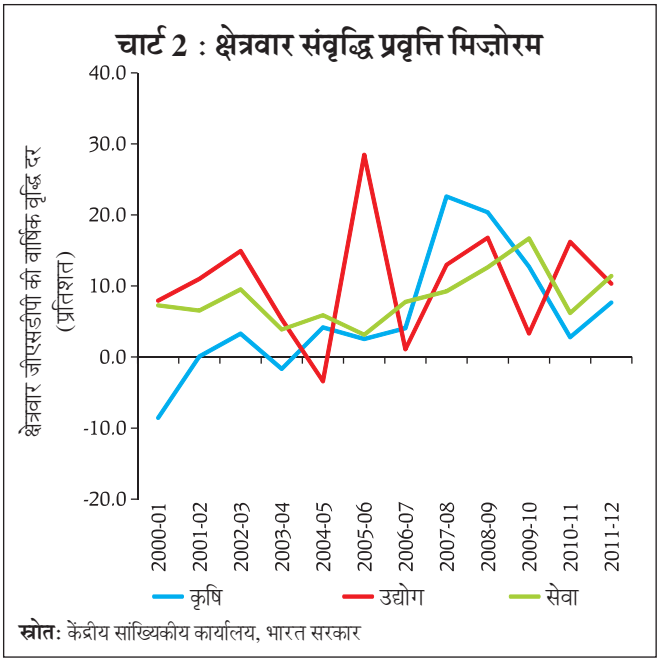

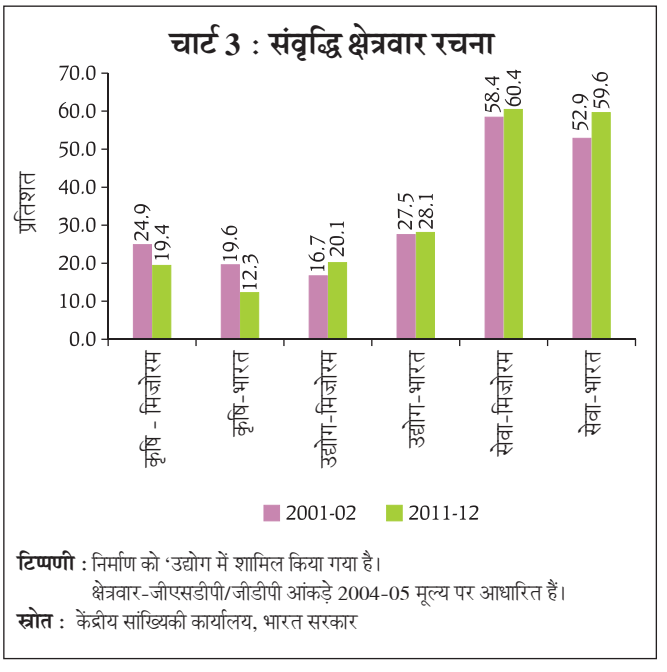

संवृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एमएसडीपी) पर पड़ा है जो 2006-07 के 26,308 रुपए से बढ़कर 2011-12 में 39,546 रुपए हो गया है (इसका मूल्य आधार वर्ष 2004-05 हैं), बावजूद इसके कि जनसंख्या में 22.8 प्रतिशत की दशकीय भारी वृद्धि हुई है जो राष्ट्रीय स्तर की जनसंख्या की 17.6 प्रतिशत वृद्धि से बहुत अधिक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011-12 के दौरान-मिज़ोरम की प्रति व्यक्ति आय 4.0 प्रतिशत थी जो औसत राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से ऊंची है (चार्ट 4)।

यह नोट करने वाली बात है कि जहां मिज़ोरम की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तरह उद्योग और सेवा क्षेत्र में बढ़ती हुई हावी हो रही है वहीं बड़ा श्रमिक बल अभी भी कृषि क्षेत्र में ही जमा

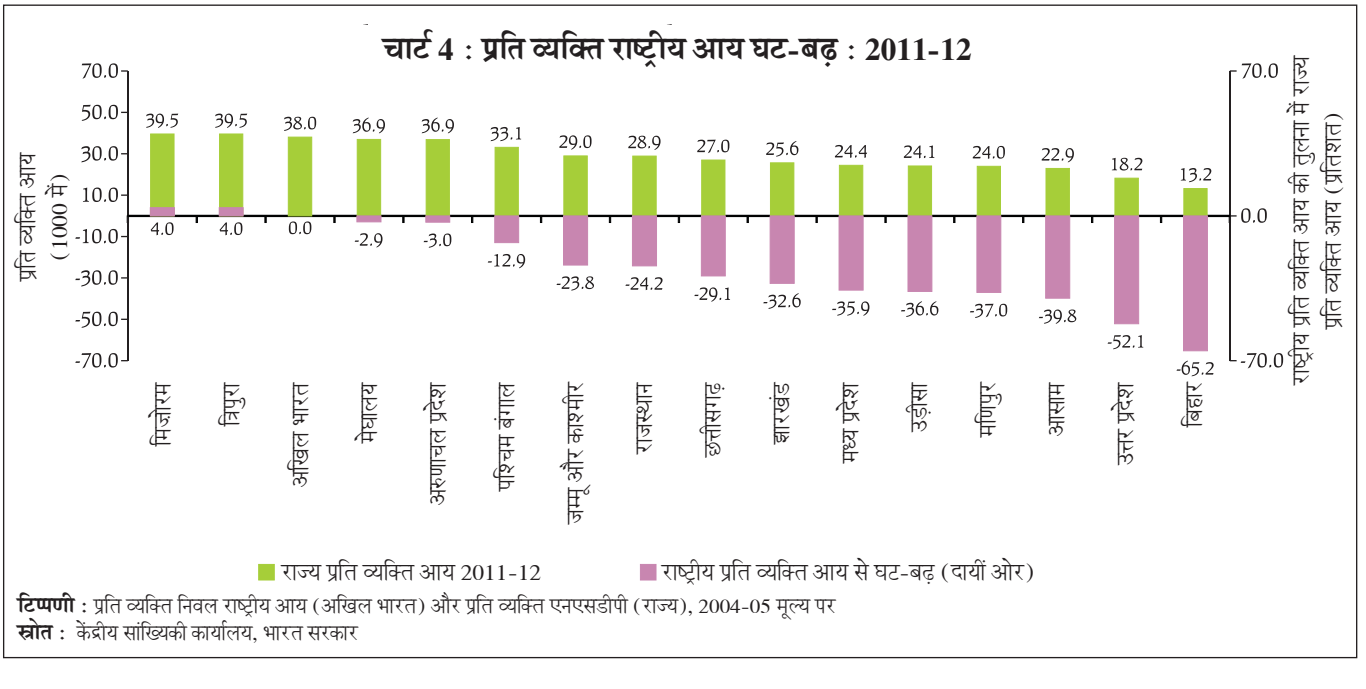

सारणी 1 : बड़े उद्योग समूह में रोजगार का हिस्सा
(सामान्य प्रमुख स्थिति)

(प्रतिशत)

गतिविधि	2013		
	मिज़ोरम	उत्तर-पूर्व	अखिल भारत
कृषि और उद्योग	47.5	50.6	49.7
खनन और खदान	0.4	0.9	0.6
विनिर्माण	4.3	6.2	10.5
बिजली	0.9	0.3	0.3
निर्माण	10.3	9.4	9.8
व्यापार	9.3	9.3	9.0
परिवहन और भंडारण	3.6	3.0	4.2
वित्त और बीमा	0.2	0.5	1.0
समुदाय सेवा	20.1	16.4	8.8
अन्य	3.4	3.5	6.1
कुल	100.0	100.0	100.0

स्रोत : श्रमिक ब्यूरो, भारत सरकार

हुआ है (सारणी 1)। इसलिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना आवश्यक हो गया है।

ग्रामीण भारत की तुलना में मिज़ोरम के ग्रामीण क्षेत्र आबादी के (15-59 आयुवाले) काम करने वाले लोगों का अनुपात अधिक है जो मिज़ोरम की संवृद्धि के लिए एक अनुकूल कारक है (चार्ट 5)। लेकिन ऐसा करने के लिए उद्योग और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ने चाहिए।

चार्ट 5 : जनसंख्या का आयु समूहवार वितरण

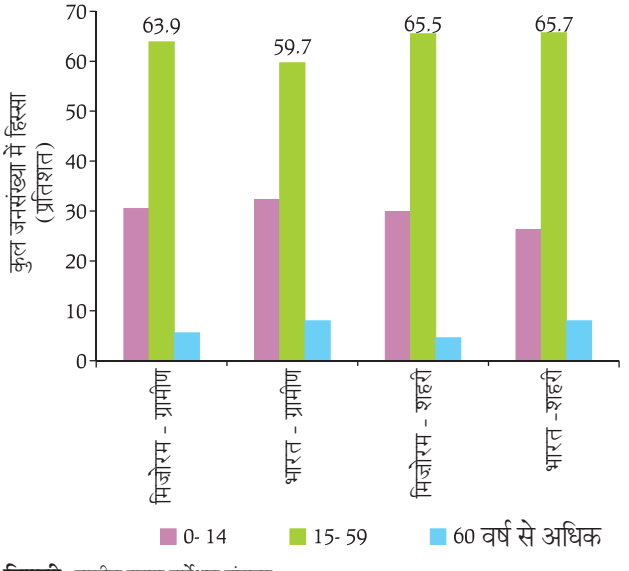

टिप्पणी: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन

चार्ट 6 : मानव विकास संकेतक

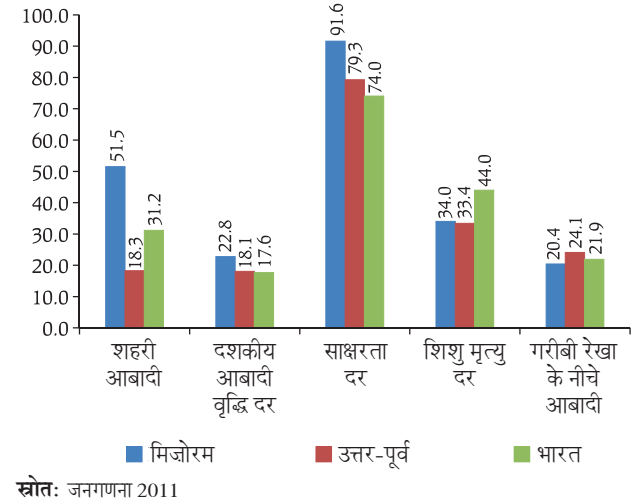

स्रोत: जनगणना 2011
वार्षिक रिपोर्ट 2012-13, गृह मंत्रालय, भारत सरकार योजना आयोग, भारत सरकार, भारत मानव विकास रिपोर्ट
2011, भारत सरकार, उत्तर-पूर्व राज्यों की मानव विकास रिपोर्ट दिसंबर 2011.

सामाजिक संकेतक

बेहतर शहरीकरण और उच्च साक्षरता की वजह से मिज़ोरम में मानव विकास का संकेतक राष्ट्रीय औसत से अच्छा है (चार्ट 6)।

मिज़ोरम में बुनियादी सुविधाएं जैसे - बिजली, टेलीविजन, कंप्यूटर, टेलीफोन और कार की गृहस्थों में उपलब्धता की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है (सारणी 2)। हालांकि, दूसरी ओर बैंकिंग सुविधाओं तक जितनी आबादी की पहुंच है उसका अनुपात यद्यपि 2001-2011 के दशक में बढ़ा है किंतु राष्ट्रीय स्तर से कम है। विकास के संदर्भ में वित्तीय समावेशन के बढ़ते ज़ोर में यह एक नीतिगत चुनौती है।

राज्य वित्त

मिज़ोरम, विशेष श्रेणी के ''राज्यों में से एक है जिनकी विशेषता कम संसाधन आधार और भौगोलिक स्थिति, बिखरा हुआ भूभाग, तथा दूरस्थ होने के नाते लागत की मजबूरी है। इन अभावों को देखते हुए, केंद्र, संसाधनों को पैदा करने के लिए केंद्रीय राशि से विशेष रकम प्रदान करती है।

मिज़ोरम के राजस्व में मिजोरम एफआरबीएम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियम-आधारित राजकोषीय नीति की वजह से अत्यधिक वृद्धि हुई है। किंतु यह सुधार काफी हद तक केंद्र से

सारणी 2 : जीवन स्तर संकेतक : मिज़ोरम और भारत

(गृहस्थों का प्रतिशत)

श्रेणी	मिज़ोरम		भारत	
	2001	2011	2001	2011
	सुविधाएं			
परिसर में पीने का पानी	19.6	31.2	39.0	46.6
बिजली	69.6	84.2	55.9	67.3
परिसर में प्रसाधन सुविधा	-	91.9	36.4	46.9
	परिसंपत्तियां			
टेलिवीज़न	20.4	55.1	31.6	47.2
कंप्यूटर	-	15.2	-	9.5
टेलीफोन	14.1	72.7	9.1	63.2
दुपहिया	6.2	13.8	11.7	21.0
कार	3.4	7.3	2.5	4.7
	सुविधाएं			
बैंकिंग	31.8	54.9	35.5	58.7
	गृहस्थ			
गृहस्थ (मिलियन में)	0.16	0.22	192.0	246.7

स्रोत : जनगणना 2011, भारत सरकार
टिप्पणी : "-" अनुपलब्ध

अंतरित राशि के कारण है क्योंकि राज्य का स्वयं का कर-राजस्व जीएसडीपी का लगभग 2.3 प्रतिशत है। संवृद्धि और रोजगार की दृष्टि से प्रमुख चिंता का विषय जीएसडीपी के अनुसार पूंजी परिव्यय में गिरावट है (सारणी 3)।

सारणी 3 : मिज़ोरम की राजकोषीय स्थिति

(जीएनडीपी के प्रतिशत के रूप में)

मद	2004-08	2008-13*	2013-14
1. राजस्व प्राप्तियां	56.2	58.6	54.8
1.1 स्वयं का कर-राजस्व	1.9	2.3	2.4
1.2 चालू अंतरण	50.8	53.7	49.5
2. राजस्व व्यय	51.9	53.9	50.6
2.1 विकासगत	33.6	36.0	35.3
2.2 ब्याज भुगतान	6.3	4.2	2.7
3. पूंजी परिव्यय	14.0	10.4	4.9
4. सामाजिक क्षेत्र व्यय	24.3	26.3	17.3
5. राजस्व घाटा	-4.3	-4.7	-4.2
6. सकल राजकोषीय घाटा	9.5	5.7	0.8
7. प्राथमिक घाटा	3.2	1.6	-1.9
8. देयताएं	105.1	74.2	55.7

* : 2012-13 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।
टिप्पणी : ऋण चिन्ह अधिशेष दर्शाता है।
स्रोत : राज्य सरकार का बजट दस्तावेज

बैंकिंग का विकास

मिज़ोरम में बैंकिंग क्षेत्र का फैलाव वहां की खास विशेषता जटिल ऊंचे-नीचे भूभाग और आर्थिक ढांचे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कृषि का काम पहाड़ियों एवं चोटियों पर होता है और सूक्ष्म लघु इकाइयों की उद्योग में भरमार है। मिज़ोरम में प्रति बैंक शाखा आबादी जून 2001 में 11,400 थी जो जून 2013 में घटकर 9,100 हो गई, और इस प्रकार से पूरे भारत के औसत 11,800 से काफी कम है जो यह दर्शाता है कि बैंकिंग सेवाओं का कवरेज बेहतर है (चार्ट 7)।

किंतु, ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात पूरे भारत के औसत से काफी कम है (चार्ट 8)। मिज़ोरम में सी-डी अनुपात हाल के वर्षों में घटा है, इसका कुछ कारण यह हो सकता है कि जमा में काफी तेजी से वृद्धि हुई है।

मिज़ोरम की वार्षिक जमा में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। किंतु ऋण की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत 2007-08 के बाद घटी गई है (चार्ट 9)। यह इस बात की आवश्यकता को प्रदर्शित करती है कि ऋण संबंधी जानकारी का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए। या तो यह मांग की या फिर आपूर्ति की कमी है जो ऋण के प्रवाह को बाधित कर रही है?

ऋण का धीमा प्रवाह, जीडीपी अनुपात के प्रति ऋण के अनुपात को प्रतिबिंबित करता है जो वित्तीय गहनता का एक अन्य उपाय है।

चार्ट 7 : बैंकिंग कवरेज की प्रवृत्ति

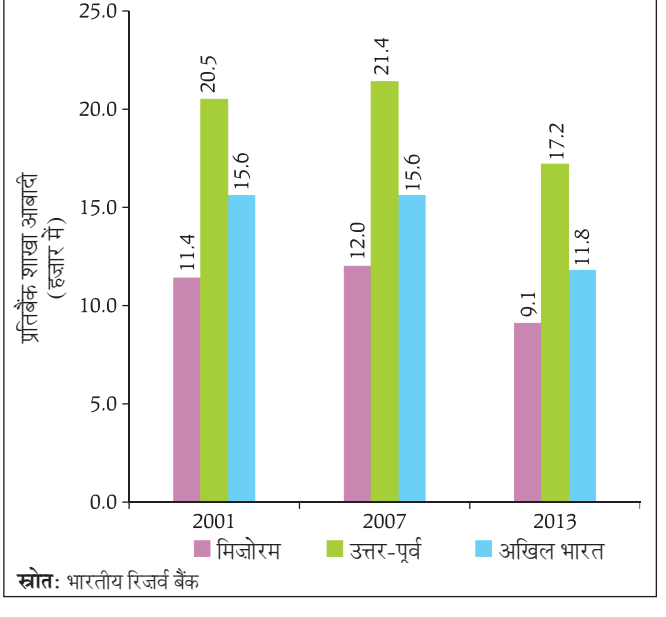

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट 8 : सी-डी अनुपात की प्रवृत्ति

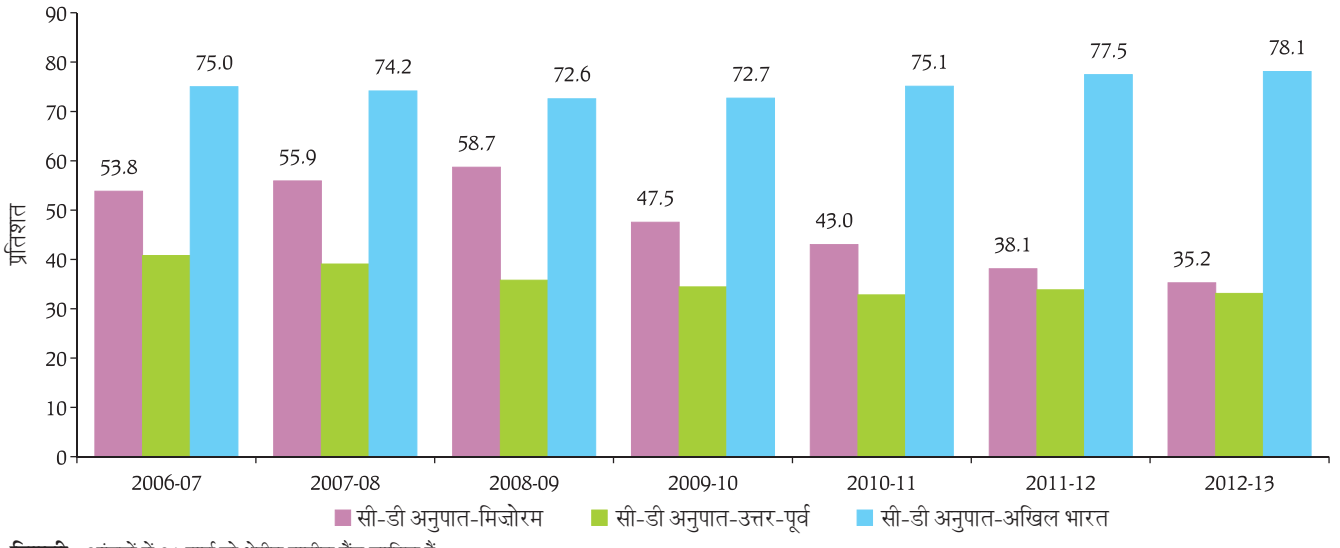

टिप्पणी : आंकडों में 31 मार्च को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

मिज़ोरम में ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2004-05 में 13.7 प्रतिशत था जो 2011-12 में संतुलित रूप से बढ़कर 18.7 प्रतिशत हो गया, इसकी तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 39.0 प्रतिशत से 57.3 प्रतिशत थी।

वित्तीय समावेशन

भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय समावेशन के प्रति कटिबद्ध है ताकि बैंकिंग सेवाएं समाज के हर तबके को पहुंच सकें। समावेशी वृद्धि और विकास के लिए यह ज़रूरी है कि गरीब और शोषित आबादी को बैंकिंग के दायरे में लाया जाए। इस संबंध में रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें बैंक-जनित मॉडल के माध्यम से उपयुक्त प्रौद्योगिकी, सेवा देने का बदलता तरीका और बढ़ती हुई वित्तीय साक्षरता की सहायता ली गई है। इस संदर्भ में, मैं चार प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

चार्ट 9 : जमा और ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति

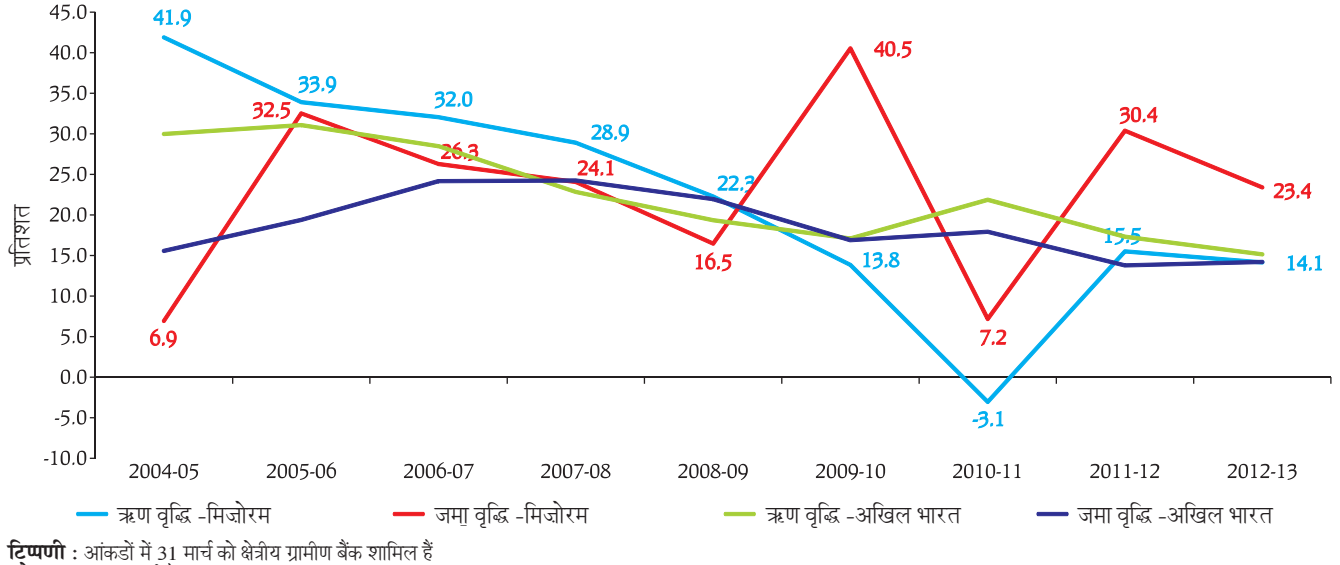

टिप्पणी : आंकडों में 31 मार्च को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट 10 : ऋण का फैलाव

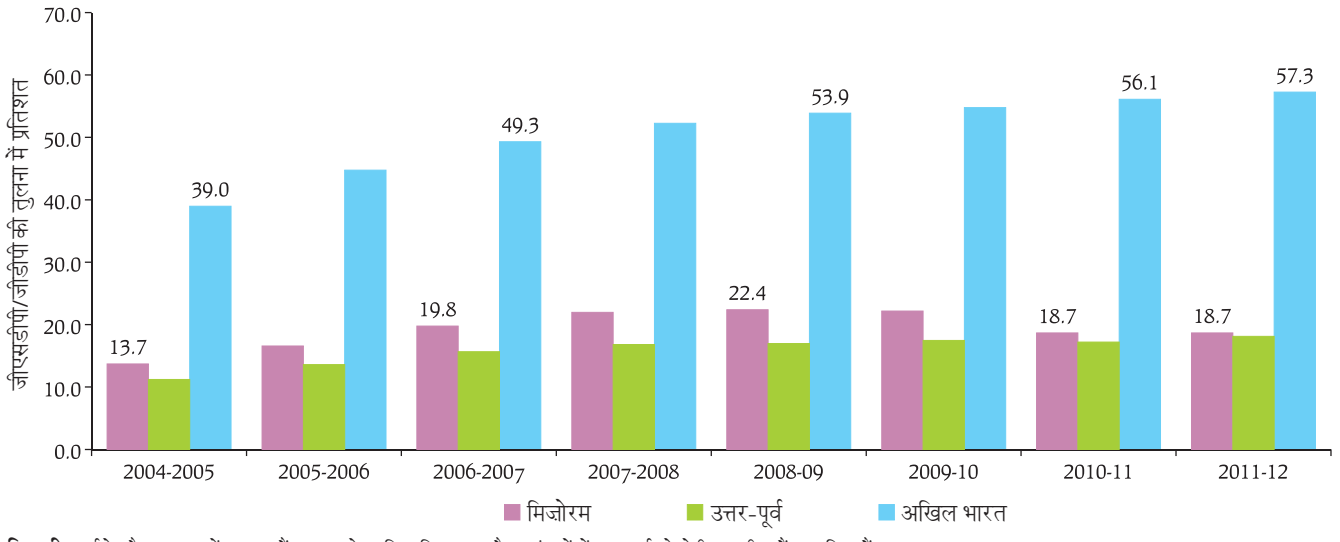

टिप्पणी: वर्ष के दौरान राज्य में प्रयुक्त बैंक ऋण को शामिल किया गया है। आंकड़ों में 31 मार्च को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रथम, बैंकों को गांवों में बैंक शाखा खोलने की आज़ादी देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार सुनिश्चित करना। हाल में, शाखा प्राधिकरण नीति को पूरी तरह उदार बना दिया गया है, बशर्ते कि बैंक कम से कम 25 प्रतिशत अपनी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलें। रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को कारोबार संपर्की के माध्यम से परिचालन की अनुमति दी है, अतः बैंकिंग को ग्रामीण क्षेत्र में दरवाज़े तक ले जाया जा रहा है।

द्वितीय, युनिवर्सल कवरेज प्रदान करने और आधार पहचान के द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को सहज बनाते हुए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 2013-16 के लिए अपनी वित्तीय समावेशन योजना तैयार करें जिसमें अधिक ज़ोर बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों पर शाखाएं खोलने पर दिया जाए।

तृतीय, उपयुक्त वित्तीय उत्पाद जो आबादी के कमज़ोर वर्ग के लिए जैसे-सादा खाता, जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ऋण उपलब्धता। इसके अलावा, बैंक खाता खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवासी) मानदडों में खासतौर से ग्रामीण और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए रियायत दी गई है।

अंतिम, वित्तीय साक्षरता के प्रसार के लिए किए गए प्रयास, इंटरनेट आधारित पाठ्यक्रम की सहायता से स्कूलों में वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय साक्षरता कैम्प का आयोजन करने जैसे प्रयास करना।

इस दिशा में, बैंकों ने उन सभी बैंकरहित गांवों को कवर कर लिया है जिनकी आबादी 2000 से अधिक है। इस आंदोलन के दूसरे चरण में 2000 से कम आबादी वाले 4,90,000 गांवों में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने का लक्ष्य है। शिनाख्त किए गए गांवों को विभिन्न बैंकों को आबंटित किया गया है कि वे प्रत्येक गांव में एक बैंकिंग - सेवा केंद्र की उपलब्धता सुनिश्चित करें। हाल के वित्तीय समावेशन अभियान की उपलब्धि के ब्योरे सारणी 4 में दिए गए हैं।

मिज़ोरम में वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति

भौगोलिक स्थिति की चुनौतियों और गहन बैंकिंग आउटरीच के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्थान की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे भारत के उत्तरी-पूर्व में वित्तीय समावेशन के लिए विशेष उपाय करें। दिसंबर, 2009 से देश के घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) इस क्षेत्र में रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर शाखा खोलने की अनुमति दी गई है। अब मैं खासतौर से मिज़ोरम में वित्तीय समावेशन की प्रगति पर बात करूंगा।

मिज़ोरम में अपनाई गई वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) के तहत राज्य के ऐसे सभी गांव जिनकी जनसंख्या 2000 या उससे अधिक थी, में मार्च 2012 के अंत तक बैंकिंग सुविधाएं, मुहैया करा दी गई थीं। ऐसे 700 गांवों की पहचान की गई है जिनकी आबादी 2000 से कम है। इन गांवों में से 106 गांवों में

सारणी 4 : वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत हुई - प्रगति

क्र.सं.	विवरण	मार्च 2010	मार्च 2013
1	**गांवों में बैंकिंग दुकानें > 2000**	**37,949**	**1,19,453**
2	**गांवों में बैंकिंग दुकानें <2000**	**29,745**	**1,49,001**
3	गांवों में बैंकिंग दुकानें - शाखाएं	33,378	40,837
4	गांवों में बैंकिंग दुकानें - कारोबार संपर्की	34,174	2,21,341
5	गांवों में बैंकिंग दुकानें - अन्य तरीके	142	6,276
6	**गांवों में बैंकिंग दुकानें - कुल**	**67,694**	**2,68,454**
7	कारोबार संपर्की मॉडल से कवर किए गए शहरी स्थान	447	27,143
8	शाखाओं के माध्यम से बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएलबीडीए) (संख्या मिलियन में)	60	101
9	शाखाओं के माध्यम से बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएलबीडीए) (राशि बिलियन रुपए में)	44	165
10	कारोबार संपर्की माध्यम से बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएलबीडीए) (संख्या मिलियन में)	13	81
11	कारोबारी संपर्की माध्यम से बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएलबीडीए) (राशि बिलियन रुपए में)	11	18
12	कुल बीएलबीडीए (संख्या मिलियन में)	73	182
13	कुल बीएलबीडीए (राशि बिलियन रुपए में)	55	183
14	बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (संख्या मिलियन में)	0.2	4
15	बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (राशि बिलियन रुपए में)	0.1	2
16	कुल किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या मिलियन में)	24	34
17	कुल किसान क्रेडिट कार्ड (राशि बिलियन रुपए में)	1,240	2,623
18	कुल जीसीसी (संख्या मिलियन में)	1	4
19	कुल जीसीसी (राशि बिलियन रुपए में)	35	76
20	आइसीटी खाते - कुल लेनदेन (संख्या मिलियन में)	27	250
21	आइसीटी खाते - कुल लेनदेन (राशि बिलियन रुपए में)	7	234

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

पक्के मकान में बैंकिंग सेवा केंद्र मॉडल अपनाए जाएंगे और शेष में कारोबार संपर्की मॉडल अपनाया जाएगा।

सितंबर, 2013 के अंत तक मिज़ोरम में 2,27,812 बुनियादी बचत बैंक जमा खाता थे, जबकि वर्ष 2013 में 10,777 ओवरड्राफ्ट सुविधावाले ऐसे खाते खोले जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा, 2013-14 में गृहस्थों को 11,642 किसान क्रेडिट कार्ड और जीसी कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के 8 जिलों से अभी तक 5 में वित्तीय साक्षरता केंद्र खोले गए हैं। सितंबर 2013 के अंत तक कुल मिलाकर 3,063 स्वयं सहायता समूहों को ऋण-सुविधा से जोड़ा गया और उन्हें कुल 1,650 लाख रुपए का कुल ऋण प्रदान किया गया।

नीतिगत चुनौती

मिज़ोरम की अर्थव्यवस्था का निष्पादन हाल के वर्षों में अच्छा रहा है। किंतु, युवा आबादी और उच्च शिक्षा स्तर तथा लोकेशन की अनुकूल स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां भी वृद्धि और विकास की अपार संभावनाएं हैं। मैं कुछेक चुनौतियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

पहली, मिज़ोरम की अधिकांश खेती पर्वतों एवं पहाड़ियों में होती है जिसमें ढलान लिए हुए छोटे-छोटे खेत होते हैं और जिनमें खेती का काम वर्षा पर निर्भर होता हैं। यही ज़मीन काफी हद उनकी रोजी-रोटी की खेती है। खेती योग्य ऐसी ज़मीन का विस्तार करना जिसे वातावरण के अनुसार बनाए रखा जा सके, अत्यधिक सीमित हैं। इसलिए कृषि में अधिक मूल्यवान बागबानी का कार्य हो सकता है जिसमें विकास की काफी संभावनाएं हैं। इसके लिए कृषि में काफी ऋण लगाए जाने की आवश्यकता है।

दूसरी, मिज़ोरम में औद्योगिक विकास 1990 के दशक में काफी विलंब से, विशेष रूप से उसे राज्य का दर्जा मिलने के बाद प्रारंभ हुआ। औद्योगिक परिदृश्य में सूक्ष्म और लघु उद्योगों का

वर्चस्व है। यहां इस बात की आवश्यकता है कि उन्हें बाज़ार से एवं औपचारिक ऋण-सुविधा की प्रक्रिया से जोड़ा जाए।

तीसरी, शेष भारत के साथ बाज़ार का जुड़ाव बहुत कमज़ोर है तथा सड़कें अच्छी नहीं हैं और रेल का नेटवर्क न होने से वस्तुओं की प्रभावी मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए, बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देनी होगी, खासतौर से सड़कें बनानी होंगी तथा फसल कटने के बाद की व्यवस्था का प्रावधान करना होगा, शीतगृह एवं प्रोसोसिंग सुविधाएं देनी होंगी।

जल-विद्युत क्षमता और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। बेहतर पहुंच-सुविधा से सेवाक्षेत्र के विकास को मदद मिलेगी, विशेष रूप से पर्यटन को, जो रोजगार और राजस्व का बढ़िया स्रोत साबित हो सकता है।

अंतिम चुनौती यह है कि राज्य की प्राकृतिक स्थिति और बुनियादी ढांचे की कमी दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग और वित्तीय ढांचे के विकास में बाधक बने हुए हैं। अतः, ज़रूरत है कि प्रौद्योगिकी पर निर्भरता बढ़ाई जाए ताकि बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच आबादी के बड़े हिस्से तक हो सके। इसके लिए दूर संचार सुविधा को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे राज्य के वित्तीय समावेशन के बारे में विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। मुझे उम्मीद है कि कल तन्हरिल गांव में हमारे आउटरीच कार्यक्रम आप में से कई लोग मौजूद होंगे। राज्य प्रशासन, बैंक और रिज़र्व बैंक मिलकर संयुक्त रूप से वित्तीय समावेशन को प्रभावी बना सकते हैं।